ISSN-2230-7540

भारत-पाकिस्तान संबंध

Survind Kumar*

Department of Political Science,

B.R.A. Bihar University,

Muzaffarpur

सार

दक्षिण एशिया में दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। इस गरीबी के बेहद जटिल कारण हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि दक्षिण एशिया दुनिया में आर्थिक रूप से सबसे कम संगठित क्षेत्र भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां की राजनीतिक यहाँ के भूगोल और इतिहास से फायदे लेने की प्रवृत्ति से काफी अधिक प्रेरित है। भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता दक्षिण एशियाई देशों से अपने आर्थिक क्रियाकलापों को निरंतर विस्तार देना होनी चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अलग हुआ था। भारत पाकिसान के साथ भाषाई सांस्कृतिक भौगोलिक आर्थिक और जातीय सम्बन्ध साझा करता है लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते आपसी मतभेद शत्रुता और संदेह के कारण पिछले 72 सालों से बेहतर नहीं हो पाए हैं। आज़ादी के बाद से अब तक भारत-पाकिस्तान के बीच चार युद्ध हो चुके हैं।

शब्द कुंजी – *दक्षिण एशिया, कश्मीर, अक्साई चिन, सिंधु जल समझौता, सियाचिन ग्लेशियर*

DISCUSSION:

भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति है, लेकिन इस स्थिति के कारण उसके समक्ष सामरिक चुनौती भी खड़ी होती है। एक तरफ जहां भारत एक आर्थिक शक्ति, जिसके आर्थिक और सामाजिक लाभ इसके पड़ोसी देशों को भी मिल सकते हैं, वहीं हम इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकते कि दक्षिण एशिया में अंतरदेशीय संबंधों का इतिहास इस तरह का है कि भारत के पड़ोसी देशों में उसकी तरक्की या प्रभाव से एक तरह का खौफ भी व्याप्त है।

INDO-PAK CONFLICTS:-

पाक अधिकृत कश्मीर:- कश्मीर राज्य के पूर्व महाराज हरि सिंह देश के तत्कालीन गर्वनर जनरल माउंटबेटन का वह प्रस्ताव मान गए थे, जिसमें कश्मीर का विलय भारत में किया जाना था। तब भारत सरकार ने इस राज्य की रक्षा कबाइली आक्रमणकारियों से की थी। लिहाजा हमारा देश पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है पर पाकिस्तान का मत इससे अलग है। वह *1933* के उस प्रस्ताव को मानता है, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान का गठन उन पांच मुस्लिम बहुल राज्यों से होगा, जो देश के उत्तर में है। पाकिस्तान इन राज्यों में कश्मीर के होने का दावा

भी लगातार करता रहा है। हालांकि इस विवाद के निपटारे के लिए लगातार प्रयास हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय मदद भी ली गई है। देश के पहले प्रधनमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। तब सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान को अपनी सेना कश्मीर से हटाने के निर्देश दिए थे, पास्तिान ने वहाँ से सेना नहीं हटाई। नतीजन पाक के कब्जे पाले कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) मान लिया गया। पाकिस्तान ने *1963* में हुंजा-मिलगित का एक भाग रस्कम और बल्तिस्तान की शक्स्गम घाटी क्षेत्र चीन को सौंप दिया। *3,800* वर्ग किलोमीटर का यह हिस्सा अब ट्रांसय काराकोरम ट्रैक्ट कहलाने लगा है, जिस पर चीन का नियंत्रण है।

अक्साई चिनः- देश के उत्तरी हिस्सों में विवाद की एक वजह अक्साई चिन भी है। बेशक यह पाक अधिकृत कश्मीर से बाहर का क्षेत्र है, पर जम्मू कश्मीर का इलाका होने की वजह से इस पर भारत का अधिकार होना चाहिए था। *1962* के युद्ध में भारत को मिली हार के बाद चीन ने इस *38* हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। वह इसे झिजियांग प्रदेश का हिस्सा बताता है। अक्साई चिन विराना और बर्फीला इलाका है। यह जम्मू-कश्मीर का सबसे पूर्वी छोर है और लद्दाख क्षेत्र से मिलता है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाके में चीन ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया है, ताकि तिब्बत और झिजियांग तक उसकी पहंुच आसानी से हो सके। हालांकि यही राजमार्ग भारत-चीन युद्ध की एक बड़ा वजह बना था। आज यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का काम करता है।

जल विवादः- दोनों देशों के बीच प्रमुख विवादों में जल बंटवारा एक प्रमुख विवाद है। जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच *1960* में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को तीन पूर्वी नदियों और पाकिस्तान ने भारत को तीन पश्चिमी नदियों के जल के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। लेकिन जल विवाद के मामले ने जब तूल पकड़ लिया जब भारत ने चिनाब नदी पर कुछ नई परियोजनाएं बनाने की पहल की। पाकिस्तान का आरोप है कि शिनगंगा परियोजना को शुरू कर भारत ने सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन किया है और इससे नदी में पानी का बहाव कम हो जाएगा।

सियाचिन ग्लेशियरः- सियाचिन ग्लेशियर हिमालय पूर्वी काराकोरम रेंज में भारत-पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यह काराकोरम के पाँच बड़े हिमनदों में सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह विश्व का सबसे बड़ा ऊँचा युद्ध क्षेत्र है। यहां सेनाएं तैनात रखना दोनों ही देशों के लिए महंसा सौदा साबित हो रहा है। तकरीबन *18,000* फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य गतिविधियाँ बंद करने को दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला।

सर क्रीकः- सर क्रीक खाड़ी गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान में सिंध की सीमा के पास है। दोनों देशों के बीच विवाद कच्छ के रण में *96* किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के सेनापति चाल्र्स नैपियर ने *1842* में सिंध जीतने के बाद उस प्रदेश का प्रशासन मुंबई राज्य को सौंप दिया था। इसके बाद सिंध में अपना प्रशासन चला रही अंग्रेज सरकार ने सिंध और मुंबई प्रांत के बीच सीमा रेखा खींची थी जो कच्छ के मध्य से गुजरती थी। इसमें यह संपूर्ण खाड़ी सिंध प्रांत में दिखाई गई थी। यानी कच्छ के मूल प्रदेश से उसे अलग कर सिंध में जोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ दिल्ली के अंग्रेज सरकार अपने अधिकृत नक्शे में सिंध और कच्छ के बीच की सीमारेखा को कच्छ के रण तक खींचने के बाद खाड़ी के प्रदेश के पास अटका कर दिखाती थी। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने खाड़ी के प्रदेश पर अपना मालिकाना हक जताया। इसके जबाब में भारत का प्रस्ताव था कि कच्छ के रण से लेकर खाड़ी के मुख तक की एक सीधी रेखा को सीमा रेखा मान लेना चाहिए लेकिन यह प्रस्ताव पाकिस्तान को मंजूर नहीं था।

पाकिस्तान

पाकिस्तान के मामले में बुनियादी रणनीतिक चुनौती दोहरी है। एक तरफ तो हमें उसमें अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए काम करना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा थोपी जाने वाली मुसीबतों का मुकाबला भी करना है। यही वजह है कि कि पाकिस्तान केंद्रित भारतीय नजरिये में समय-समय पर उतार-चढ़ाव दिखता रहा है। कभी हमारा रवैया उसके साथ बेहद गर्मजोशी भरा रहता है, तो कभी यह बिल्कुल संबंध विच्छेद-सी स्थिति में खड़ा दिखता है। पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते को उसके द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों से जोड़ने की भारतीय कोशिश को कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। इस तरह की रणनीति से बाहर निकलने के लिए हमें सकारात्मक व नकारात्मक उत्तोलकों वाले

ISSN-2230-7540

बीच के विकल्पों की जरूरत होगी। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान, जिसमें वहां की फौज, आईएसआई और नौकरशाह व सियासी बौद्धिक शामिल हैं, यह समझता है कि सीमा-पार आतंकवाद ही वह रास्ता है, जो भारत को पाकिस्तान से राफ्ता रखने और उसके हितों को मानने के लिए मजबूर करेगा। उनमें प्राथमिकताओं को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी बौद्धिक वर्ग के विभिन्न खेमों के रवैये और सोच में कोई अंतर नहीं है। भारत-पाकिस्तान के संबंधों में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव अहिस्ता-अहिस्ता ही आएगा। यानी यदि वाकई दोनों मुल्कों के बीच मधुर सामंजस्य की कोई स्थिति मुमकिन दिखती है, तो वह इस रिश्ते की छोटी-छोटी कामयाबियों की पराकाष्ठा ही होगी, किसी इकलौती ऐतिहासिक कवायद की देन नहीं।

हलांकि पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के लिए हमें अमेरिकी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हमारे संदर्भ में अपनी विदेश नीति में जिस हथियार का कामयाबी से इस्तेमाल करता रहा है, उससे उसे रोकने के लिए हम अमेरिकी समर्थन पर ही निर्भर नहीं रह सकते। जब तक अमेरिकी चिंताओं के अनुरूप पाकिस्तान अल-कायदा व तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ता हुआ दिखेगा, आधे मन से ही सही, तब तक अमेरिका उससे सिर्फ जबानी अपील भर करेगा कि वह भारत के खिलाफ सीता पार आतंकवाद को रोकने के अपने वादे को निभाए। निस्संदेह, पाकिस्तान को दबाव में रखने के हमें जिस हद तक अमेरिकी चाबी की जरूरत हो, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि सीमा पार आतंकवाद की पाकिस्तानी नीति से निपटाने में इस चाबी की भी सीमित भूमिका है।

चीन के साथ पाकिस्तान की 'सदाबहार मित्रता' उसे उसकी भारत विरोधी नीतियों के लिए दुनिया के नकारात्मक परिणामों से बचती रही है। क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा चीन पाकिस्तान के लिए एक अधिक मजबूत ढ़ाल का काम करता रहेगा। यह सही है कि पाकिस्तान में जिहादी कट्टरता के फैलने से पैदा होने वाले खतरे को लेकर चीन की अपनी भी चिंताएं हैं। इस संबंध में चीन अपनी नाराजगी पाकिस्तान से जता सकता है, यहाँ तक कि वह भारत के साथ अपनी चिंताओं और मांगों पर पाकिस्तान हमेश ही बेहद तेजी से कदम उठाता है। यह सोचना गलत होगा कि पास्स्तिान में 'स्थिरता' लाने या फिर वहां के जेहादी खतरों से निपटने के लिए हम चीन के साथ सहयोग कर सकते हैं। यदि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी कम हुई और पाकिस्तान अपने खुदमुख्तार हो चले इलाकों पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटा, तो बहुत मुमकिन है कि हमें पाकिस्तान में चीन की कहीं अधिक सक्रिय भूमिका देखने को मिले। परिणामस्वरूप, ऐसा भी हो सकता है कि चीन की तरफ से पेश व्यापक रणनीतिक चुनौतियों से हमें पाकिस्तान को एक सब सेट के रूप में देखने की जरूरत पड़े। हमें निश्चित रूप से चीन को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान पर कुछ दबाब तो बन ही सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका सिर्फ क्षणिक महत्व होता है और इसकी उपयोगिता भी सीमित होती है।

दोनों तरफ परमाणु हथियारों की मौजूदगी हमारे रणनीति को नियंत्रित करती है। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि उसके परमाणु हथियार भारत को किसी तरह के प्रतिशोध की कार्रवाई की शुरूआत करने से रोकेंगे, वरना जो नाभिकीय युद्ध स्तर तक जा सकता है। पाकिस्तान का अंदरूनी स्थायित्व मौजूदा दिशाहीन स्थिति में ही पड़ा रहता है या फिर वह वाकई एक ठोस सकारात्मक रूप लेता है अथवा और गर्त में जाता है, यह मुख्य रूप से उसकी भीतरी ताकतें ही तय करेंगी। भारत इसमें न तो कुछ जोड़ सकता है और न ही घटा सकता है। लेकिन इसके लिए दो लक्ष्यों पर काम जरूरी है। एक, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पाकिस्तान स्थित कोई आतंकि समूह भारतीय सीमा के अंदर किसी गंभीर आतंकी वारदात को अंजाम न देने पाए। दूसरे, हमें एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है, जिसमें दोनों पक्ष पूरे भरोसे और ऐतबार के साथ गहरे व पेचीदा विवादों को सुलझाने की पहल करें। ऐसा करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक उत्तोलकों को गढ़ना और इस्तेमाल करना होगा।

नकारात्मक उत्तोलक

नकारात्मक उत्तोलक का लक्ष्य पाकिस्तान को यह बताना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर व न सिर्फ भारत के साथ अपने नापाक इरादों में असफल रहेगा, बल्कि इस तरह के प्रयासों से वह खुद के हितों को ही चोट पहुंचाएगा, जैसा कि वहाँ के संपन्न लोग अब समझने लगे हैं। भारत अगर इस तरह की रणनीति अपनाता है कि तो पाकिस्तान को इस तरह की हरकत में अपनी लिप्तता से इनकार करने के लिए बेहद ठोस रणनीति की जरूरत होगी। और हमें भारतीय जमीन से किसी भी तरह के बड़े आतंकी हमले को असफल करने की पूरी तैयारी करने की भी जरूरत है। हम ऐसा हमारी पुलिस, खुफिया और अपनी आतंकवाद निरोधक क्षमताओं को बढ़ाकर ही कर सकते हैं। समय के साथ जिहादी

ISSN-2230-7540

संगठनों की इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देने की क्षमता कम हो जाएगी और इस तरह से पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भी इस तरह के हमलों को सहायता देने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

सकारात्मक उत्तोलक

सकारात्मक उत्तोलक का मकसद फौरन ऐसी प्रेरणा पैदा करना होगा जिससे पाकिस्तान भारत की चिंताओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाए। साथ ही इसका मकसद पाकिस्तान के साथ रिश्तों के सुधार और सामान्यीकरण के लिए एक जमीन तैयार करना भी होगा। इन सकारात्मक उत्तोलकों का प्रयोग हमें ऊपर बताए गए नकारात्मक उत्तोलकों के साथ करना होगा।

पाकिस्तान के साथ व्यापक वार्ता के लिए हमने यह शर्त लगाने की नीति अपनाई हुई है कि पहले वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन इस नीति के वांछित परिणाम अभी तक मिले नहीं हैं। इससे पाकिस्तान को अपनी राह पर चलजते जाने के और ज्यादा मौके मिलते हैं। इसके साथ वह गैर जरूरी प्रतीकात्मकता के साथ व्यापक बातचीत का विचार देता है। जाहिर है, हमें बातचीत के प्रतीकात्मक महत्व को कम करने के लिए काम करना चाहिए और इसे इस तरह पेशन करना चाहिए कि यह सामान्य कूटनीति से ज्यादा कुछ भी नहीं है।

किसी बड़े उकसावे की घटना होने पर बातचीत बंद करने के बजाय हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि हम बातचीत को जारी रखने के पक्ष में है। हमें यह संदेश देना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर बातचीत के सभी तरीकों को बनाए रखने की आवश्यकता है और ऐसा करके ही सभी गलतफहमियां और गलत सोंच से बचा जा सकता है और स्पष्टता के साथ अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन हमें पाकिस्तान को बिना किसी लाग-लपेट यह भी बता देना चाहिए कि मोल-तोल और वार्ता की वास्तविक गति उसके व्यवहार पर ही निर्भर होगी। बातचीत में भाग लेने की हमारी इच्छा के अतिनिरक्त फायदे भी होंगे। इससे हम भारत-पाक वार्ता में बाहरी स्वार्थ और हस्तक्षेप को पहले से ही रोक पाने में कामयाब होंगें। पिछले रास्तों से होने वाले मोल-भाव और पाकिस्तानी सेना के साथ सीधे बातचीत के साथ-साथ काम करने के इस तरीके का हम सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास विविध तरीके और रास्ते हैं जिनमें परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव करके उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है।

आम पाकिस्तानी अवाम का भारत के आम लोगों के साथ जितना ज्यादा घुलना-मिलना होगा, भारत के प्रति जान-बुझकर कटुतापूर्ण नजरिया पैदा करनक अी अधिकारिक नीतियां उतनी ही कम प्रभावशाली होती जाएंगी। सिविल सोसायटी, विद्वानों, कलाकारों और विद्यार्थियों के बीच सभी स्तरों पर आपसी लेन-देन को बढ़ावा देना भारत के लिए जबर्दस्त फायदेमंद हो सकता है। लोगों के लिए सीमा के आरपार आने-जाने के लिए हम एक पक्षीय तरीका अपना सकते हैं। भले की पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई सकारात्मक जबाब न मिले, लेकिन हम इसे जारी रख सकते हैं। कुछ ऐसे एकतरफा कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए भले ही पाकिस्तान वैसा न करे। मसलन वीसा की प्रक्रिया को उदार बनाना, कोई कितनी जगहों पर घूमने जा सकता है, इससे पाबंदी हटाना, अनुकूल ताकतों को विविध प्रवेशाधिकार वीसा उपलब्ध कराना, खासकर मीडिया के लोगों को आदि। महत्वपूर्ण बात यह है कि तनाव बढ़ने की हालत में भी इन चीजों को बंद नहीं किया जाना चाहिए।

यहां जो भी तरीके सुझाए गए हैं, वे पाकिस्तान के व्यवहार को वांछित दिशा में प्रभावित करने के लिए मध्यम स्तर, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तोलक के साथ एक कूटनीतिक टूल बॉक्स का निर्माण करते हैं। इन तरीकों को किस संयोजन के साथ प्रयोग किया जाए, यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ये तरीके और क्षमताएं हमारे राजनीतिक नेतृत्व को तमाम नए ऑप्शन मुहैया कराऐंगे, तमाम उससे भी आगे के विकल्प जो अब तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

आकस्मिक घटनाएं:-

पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति इस बात को महत्वपूर्ण बनाती है कि हमें कुछ खास आकस्मिक घटनाओं के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इनमें से कुछके बारे में आगे सोचा जा सकता है लेकिन दो परिस्थितियों के बारे में अभी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। पहली परिस्थिति का सरोकार पाकिस्तान से पैदा होने वाले संभावित नाभिकीय आतंकवाद से है। गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों वाले अध्याय के नाभिकीय सुरक्षा वाले हिस्से में इस पर चर्चा की गई है।

ISSN-2230-7540

दूसरी आकस्मिक घटना जिसके लिए हमें तैयार रहना है वह है पाकिस्तान में धीरे-धीरे बढ़ती जा रही अस्थायित्व की संभावना या कोई बड़ी पर्यावरण संबंधी आपदा, जो हमारे दरवाजे पर मानवता के लिए संकट के तौर पर खड़ी दिखाई दे। क्या हमारे लिए यह संभव है कि हम अपनी सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दें? अगर नहीं है तो हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम पाकिस्तनियों की बड़ी संख्या की घुसपैठ को संभाल लेंगेे? बातचीत की कौन-सी लाइन को सेट करने की हमें आवश्यकता है जिससे हम पाकिस्तान के उन लोेगों के साथ काम कर सकें जो इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं? ये और ऐसे कुछ और सवालों पर पहले से सोच-विचार करना बेहद जरूरी है। मौजूदा समय में पाकिस्तान में चल रहे अस्थायित्व से भरे दौर को बेहद नजदीक से देखना जरूरी है।

हमें यह मानकर भी नहीं चलना चाहिए कि हर तरह का अस्थायित्व हमारे नजरिये से बुरा है। हमारे कूटनीति के लिए सबसे बड़े चुनौती उन परिणामों से निपटना है जो उसके अस्थायित्व के सामने झुकने से पैदा होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान से रिश्तों को उनकी पूरी जटिलताओं के साथ देखा जाना चाहिए।

उपमहाद्वीप में कूटनीतिक एकता को दोबार स्थापित करने के दूरगामी लक्ष्यों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह कूटनीतिक एकता दक्षिण एशिया के सभी लोगों के हितों के अनुरूप होगी। सीमित चीजों को ध्यान में रखकर या संकुचित राजनीतिक विचारों के आधर पर अपनाई गई एक सीधी-सादी सोच हमारे कूटनीतिक विकल्पों को कम करने और छांटने का ही काम करेगी।

संदर्भ:-

1. सिन्हा, अरूण (*2011*), कुमार एंड दि राइज ऑफ़ बिहार, दिल्ली; पैंगुइन इन्डिया
2. रोबीन, सीरील (*2009*), दि न्यू स्टांगहोल्ड ऑफ़ ओबीसी पॉललिटिक्स इन राइज ऑफ़ दि प्लेबिअन्स? दि चेन्जिंग फेस ऑफ़ इन्डियन लेजिसलेअिव असेम्बलीज (पृष्ठ: *85-86*). इन जाफ्रेलॉट, क्रिस्टोफ एंड कुमार, संजय (एडिट)
3. *(2014)* कुमार डिमांड भारत रत्न फॉर कर्पूरी ठाकुर, इकोनॉमिक टाइम्स, रीट्रीव्ड
4. अंसारी, फर्ज एंड अहमद, *(1994)*, रेक्विअम फॉर अ डूम्ड पार्टी. इन्डिया टूडे. रीट्रीव्ड
5. *(2008)* राजद डिफेन्ड्स लालू फॉर ऐडमिटिंग ही मेड अ मिस्टेक, टाइम्स आॅफ इन्डिया, रीट्रीव्ड
6. गायकवाड़, राही (*2013*) टूगेदर दे इन्डेड लालू' स रेन इन बिहार दि हिंदू रीट्रीव्ड
7. होजर, डब्ल्यू. (*1997*). जनरल इलेक्शन्स *1996* इन बिहार: पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रफी एंड एनर्की, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम *32*, नं. *41*,
8. अहलूवालिया, एम.एस. (*2000*) इकोनॉमिक परफॉर्मेन्स ऑफ़ स्टेट्स इन पोस्ट-रिफॉर्मर्म पीरियड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम *35*, नं. *19* रीट्रीव्ड
9. जाफ्रेलॉट, सी. (*2003*). इन्डिया स साइलेन्ट रेवलूशन: दि राइज ऑफ़ दि लोअर कोर्ट्स इन नॉर्थ इंडिया लंदन: सी हस्र्ट एंड कम्पनी
10. यादव, वाई. (*1999*). इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन दि टाइम्स ऑफ़ चेन्ज: इन्डियास थर्ड इलेकटोरल सिस्टम *1989-99*. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम. *34*, नं. *34/35*
11. क्राइम न इन्डिया (*1990* एंड *1999*) नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो, मिनीस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इन्डिया

Corresponding Author

ISSN-2230-7540

Survind Kumar*

Department of Political Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

survindkumar555@gmail.com

IGNITED MINDS Journals